



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1205/MH/25/2022-ESDW

दिनांक: 05.07.2023

श्री मनोज सौनिक,
मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र सरकार,
मंत्रालय, मैडम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरु स्कायर,
मुंबई -400032, महाराष्ट्र
ई-मेल: cs@maharashtra.gov.in

श्री प्रदिप कुमार व्यास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
आदिवासी विकास विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र - 400032,
ई-मेल: sec.tribal@maharashtra.gov.in

श्री नितिन गद्रे,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, मैडम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरु स्कायर,
मुंबई -400032, महाराष्ट्र
ई-मेल: acs.gadservices@maharashtra.gov.in


डॉ. राजेंद्र भारूड,
आयुक्त,
जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे,
महाराष्ट्र सरकार,
28, क्रीस गार्डन, बंड गार्डन रोड,
ओल्ड सर्किट हाउस के पास, कैम्प,
पुणे-411001, महाराष्ट्र,
ई-मेल: trti.mah@nic.in

विषय: गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अवैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति का लाभ उठाने के संबंध में श्री कृष्णा पराड, अध्यक्ष, औल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईस फ़ेडरेशन, शाखा, मुंबई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र की ओर से दिनांक 03.12.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री कृष्णा पराड से दिनांक 03.12.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री कृष्णा पराड,
अध्यक्ष,
औल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईस फ़ेडरेशन,
शाखा, मुंबई विश्वविद्यालय,
महाराष्ट्र

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।